

हरदीप पुरी पर शिक्ंजा कस कर मोदी सरकार को घेरने की नीति बनाई कांग्रेस ने

एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हरदीप पुरी से तुरंत त्याग पत्र देने की मांग की व कई सवाल पूछे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 फरवरी। कांग्रेस ने केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी और कुख्यात यौन अपराधी जैफ्री एप्टीन से उनके संबंधों को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि उनके पास मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी ने सवाल उठाया कि वह बार-बार एप्टीन से किसके कहने पर मिलते रहे। कांग्रेस का आरोप है कि एप्टीन भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा था। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी घेरते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी के चेहरे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस ने आज फिर दोहराया कि केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी के सेक्स अपराधी जैफ्री एप्टीन के साथ संबंधों

- खेड़ा ने पूछा, केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी किसके कहने पर बार-बार बदनाम यौन अपराधी एप्टीन से मिल रहे थे और उसे किसका संदेश दे रहे थे।
- खेड़ा ने कहा, पुरी का यह दावा बेहद बचकाना है कि उन्हें नहीं पता था कि एप्टीन एक अपराधी है। खेड़ा ने कहा, पुरी कहते हैं कि वे सिर्फ एप्टीन से मिले थे, उसके किसी कृत्य में शामिल नहीं थे, लगता है पुरी को इसका पछतावा है।
- खेड़ा ने कहा, पुरी 2014 से 2016 के बीच एप्टीन से किस हैसियत से मिले, उस समय तो वे केन्द्रीय मंत्री नहीं थे, विदेश सेवा के रिटायर्ड अफसर मात्र थे, जब कि उस समय का एक भी राजदूत कभी भी एप्टीन से नहीं मिला।
- कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि जब भारत में “डिजिटल इंडिया” अभियान शुरु भी नहीं हुआ था, उस समय पुरी ने एप्टीन से उस अभियान पर चर्चा की थी।
- कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कुख्यात यौन अपराधी एप्टीन भारत की विदेश नीति में दखल दे रहा था। फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की भारत यात्रा पर उसे गुस्सा आया था, तो क्या उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए ही प्रधानमंत्री इज़रायल गए थे?

को लेकर हुए बड़े खुलासों के बाद पुरी को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के

अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इस मामले में अपने बचाव के लिए पुरी द्वारा दिए जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी किसान नेताओं से मिले

प्र.मंत्री मोदी पर ट्रंप की टिप्पणी वाले वीडियो पर एक्शन होगा

विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर ऐसा वीडियो है, सच है या झूठ, उस पर उचित कार्यवाही होगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 फरवरी। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उस वीडियो से जुड़े सवालों का जवाब दिया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कथित तौर पर यह कहते सुने गए कि वे “मोदी का पोलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहते।” ट्रंप की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा, मैंने वह वीडियो नहीं देखा है। लेकिन यदि वास्तव में ऐसा कोई वीडियो है, चाहे वह सही हो या गलत, हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता का यह बयान एफ.बी.आई. के डायरेक्टर के साथ ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक पुरानी क्लिप फिर से सामने आने के संदर्भ में आया है, जिसमें वे मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि “मोदी एक महान व्यक्ति हैं, वे ट्रंप से प्यार करते

- ज्ञातव्य है कि हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप मोदी के बारे में कह रहे हैं, “मोदी एक महान व्यक्ति हैं, ट्रंप से प्यार करते हैं, मैं उनका राजनैतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता।-- बताया जाता है कि उक्त प्रैस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के साथ एफ बी आई के डायरैक्टर भी थे।
- प्रैस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि रूस के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं और रहेंगे।
- उन्होंने, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बताया कि अमेरिकन फैक्टशीट में संशोधन कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि ट्रेड डील पर अमेरिकी व भारतीय बयानों में अंतर था।

हैं।” उन्होंने “प्यार” शब्द की सावधानीपूर्वक व्याख्या करते हुए कहा कि “इसे किसी और अर्थ में न लिया जाए।” वीडियो में ट्रंप ने कहा, “वे एक

महान व्यक्ति हैं। मोदी एक महान व्यक्ति हैं, वे ट्रंप से प्यार करते हैं। अब, मुझे नहीं पता कि “प्यार” शब्द को आप किस तरह लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन में देशभर के किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत-

- संसद परिसर में हुई इस मीटिंग में राहुल ने किसानों के साथ इंडो-अमेरिका ट्रेड डील पर वार्ता की।

अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध करने तथा भारतीय किसानों और खेतिहार मजदूरों के अधिकारों, आय और भविष्य की रक्षा के लिए देशव्यापी जन आंदोलन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध करते हुए चेतावनी दी कि यह मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे की खेती करने वाले किसानों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत करता है।

लोकसभा की कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित

नई दिल्ली, 13 फरवरी। लोकसभा में बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को संपन्न हो गया। पीठासीन अधिकारी संघ्या राय ने सदन की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। अब बजट

- बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा व 2 अप्रैल तक चलेगा।

सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा।

लोकसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। लोकसभा के महासचिव उषल कुमार सिंह ने बताया कि औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को 12 फरवरी को राज्यसभा ने भी बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी संघ्या राय ने सदन की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

जीत मिलते ही बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी के भारत के प्रति सुर बदले

चुनावों के दौरान भारत के प्रति नरम रुख प्रदर्शित कर रहे नेताओं ने पुराने विवादों को उठाना शुरु कर दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 फरवरी। बांग्लादेश में हालिया आम चुनाव ने राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर दिया है। एक दल प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचा है और इसे व्यापक जनादेश मिला है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने देशव्यापी चुनाव में दो-तिहाई से अधिक सीटें जीत लीं। यह चुनाव उस छात्र आंदोलन के कुछ महीनों बाद हुआ है, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हसीना फिलहाल भारत में निर्वासन में हैं। लेकिन यह नई जीत भी मानो “नई बोटल में पुरानी शराब” जैसी है। चुनाव जीतते ही पार्टी के नेता तारिक रहमान ने एक बार फिर शेख हसीना को मुकदमे का सामना करने के लिए बांग्लादेश को सौंपने की मांग दोहरा दी। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भी लगातार हसीना की स्वदेश वापसी की मांग करती रही थी। अंतरिम विदेश मंत्री

- बी एन पी ने भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग की, ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।
- भारत के लिए भले ही शेख हसीना अब एक बोझ बन गई हैं, पर भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंप नहीं सकता, ऐसा करने से ना केवल बांग्लादेश को भारी कूटनीतिक बढ़त मिलेगी, बल्कि भारत की छवि भी खराब होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत अंतिम “भरोसेमंद शरणस्थली” है।
- बांग्लादेश ने नदी जल विवाद और सीमा विवाद जैसे पुराने मसले उठाए और वही पुराना राग अलापा कि उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। सत्ता के करीब पहुंच चुकी बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी के नेता जोर देकर कह रहे हैं कि भारत व बांग्लादेश को बराबरी के स्तर पर संवाद करना चाहिए।

ने भी कई बार यही माँग दोहरायी। भारत का रुख अब तक यही रहा है कि वह इन अनुरोधों की जांच कर रहा है। यह मांग व्यावहारिक रूप से जटिल है। भारत के लिए यह संभव नहीं कि वह पूर्व प्रधानमंत्री को सीधे नई सरकार के हवाले कर दे और वे मुकदमों

का सामना करें। बांग्लादेश के नेता भी इस यथार्थ से अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन घरेलू राजनीतिक दबाव उन्हें यह मांग दोहराने के लिए बाध्य करता है। यही वह पुराना गतिरोध है, जिसमें दोनों देशों के संबंध फंसे हुए हैं। हालांकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे तारिक रहमान

बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी ने कुल 350 सीटों में से अब तक 208 सीटें जीत ली हैं

- कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक पार्टी जमात व उसके सहयोगी मात्र 69 सीटें ही जीत पाए हैं।
- चुनावों की सब से खास बात, 7 महिला प्रत्याशियों की जीत रही। इनमें से 6 बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी की हैं और एक निर्दलीय है।
- बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने फिलहाल चुनाव नतीजों की घोषणा टाल दी है क्योंकि तीन सीटों में कुछ कानूनी मसले हैं।

चुनाव लड़ा था, से जीत दर्ज की। बीएनपी ने बोगुरा-7 सीट भी जीती, जो 1991 से 2008 तक हर चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जीतती रही थीं। 2014 में जब जिया ने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा था, तब यह सीट बीएनपी से छिन गई थी। जहां जमात-ए-इस्लामी दूसरे स्थान पर काफ़ी पीछे रही, वहीं इस्लामी पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने

ढाका-15 सीट से जीत हासिल की। खालिदा जिया का आखिरी प्रधानमंत्री कार्यकाल 2006 में समाप्त होने के 20 साल बाद बीएनपी दोबारा सत्ता में आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2024 में हसीना सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले ऐक्टिविस्ट द्वारा गठित और जमात-नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नेशनल

सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने जिन 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से मात्र पांच पर जीत हासिल की है। प्रोथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक सात महिला उम्मीदवारों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की है। इनमें माणिकगंज-3 से बीएनपी की अफरोजा खानम रीता, सिलहट-2 से तहसीना रश्दिर लुना, नाटोर-1 से फरजाना शारमिन, फरीदपुर-2 से शमा ओबैद इस्लाम और फरीदपुर-3 से नायाब यूसुफ अहमद शामिल हैं। बीएनपी गठबंधन की उम्मीदवार इसरत सुलताना एलेन भुट्टो ने झालाकाठी-2 से जीत दर्ज की, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रूमीन फरहाना ने ब्राह्मणबारिया-2 से विजय पाई। “ढाका ट्रिब्यून” के अनुसार, तीन सीटों में कानूनी कारणों के चलते, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के क्या मायने हैं भारत के लिए

विपक्षी पार्टी बीएनपी के साथ भारत का पुराना अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है

- विजेता बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान पहले ही कह चुके हैं कि वे “बांग्लादेश फर्स्ट” पर केन्द्रित नीति पर चलेंगे और सीमा विवाद तथा नदी जल बंटवारे पर कड़ी शर्तें लगाएंगें।
- पर, सबसे बड़ा मसला पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का है, जो सत्ता से अपदस्थ किए जाने के बाद से भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं।
- लेकिन एक बात जो भारत के पक्ष में है, वह यह कि मोहम्मद यूनुस व जमात-ए-इस्लामी का रुख ज्यादा भारत विरोधी है और बीएनपी के साथ भारत पहले डील कर चुका है तो यह अनुभव मददगार साबित होगा।

के भारत की ओर स्पष्ट झुकाव के विपरीत होगी। बीएनपी नेता और नामित प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले ही तीस्ता और पद्मा जल बंटवारे समझौतों पर कड़ा रुख दोहरा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) द्वारा “बांग्लादेश फर्स्ट” नीति अपनाने की संभावना है, जो पिछली अवामी लोग सरकार के लिए “कड़े कदम” उठाएगी।

2001 से 2006 के बीच जब बीएनपी सत्ता में थी, तब दोनों देशों के संबंध सीमा सुरक्षा मुद्दों और इस आरोप के कारण तनावपूर्ण रहे कि भारत-विरोधी समूहों को बांग्लादेश में शरण मिली हुई थी। 2004 में चटगांव-सीयूएफएल जेट्टी पर दस ट्रक हथियार बरामद होने के बाद भारतीय एजेंसियों ने चिंता जताई थी। भारतीय

एजेंसियों का कहना था कि ये हथियार पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी समूहों के लिए थे। 2013 में भारत ने तारिक रहमान को कथित रूप से कट्टरपंथी नेटवर्क और आईएसआई से नजदीकी को लेकर भी चिंता जताई थी। इसके बावजूद, बीएनपी की जीत संबंधों को फिर से सैट करने का अवसर भी प्रदान

करती है। यदि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पराजित न होती, तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता था। नई दिल्ली ने अतीत में बीएनपी के साथ संवाद किया है, हालांकि संबंध पूरी तरह सहज नहीं रहे। इसके विपरीत, नई दिल्ली ने “यूनुस सरकार के साथ आवश्यक सीमा से अधिक संवाद से परहेज” किया था। रिकॉर्ड के लिए, बीएनपी नेताओं की ओर से सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। रहमान के करीबी सलाहकार महदी अमीन के हवाले से कहा गया है: निश्चित रूप से, कुछ मुद्दे हैं। लेकिन हर मुद्दा लोगों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने का अवसर भी हो सकता है। हम आपसी विश्वास और हितों पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों की कद्र करेंगे, ऐसे पारस्परिक संबंध, जो समानता, निष्पक्षता और न्याय के साथ दोनों देशों के लिये उपयोगी रहें।

- विक्रम भट्ट व उनकी पत्नी पर फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है।

को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन विक्रम भट्ट को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में विक्रम भट्ट की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी और परिवादी डॉ. अजय मुर्दिया की ओर से एडवोकेट हर्ष सुराना ने पेरवी की। अब दोनों की नियमित जमानत पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

परिवादी डॉ. अजय मुर्दिया के वकील मंजूर हुसैन ने बताया कि 31 जनवरी 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट ने भट्ट दंपती की जमानत याचिका खारिज की थी। इसके बाद दंपती ने सुप्रीम कोर्ट जाकर नियमित जमानत के लिए स्पेशल लीव पिटिशन दायर की थी।